

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] No. 20]

नई दिल्ली, बुधवार , फरवरी 23, 2000/फाल्गुन 4, 1921 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2000/PHALGUNA 4, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2000

सं. टीएएमपी/8/2000-सामान्य.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार प्रयोक्ताओं द्वारा विलंब से किए जाने वाले भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज और पत्तन न्यास द्वारा विलंब से की जाने वाली वापसी अदायगियों पर भी दंडात्मक ब्याज निर्धारित करता है।

मामला सं. टीएएमपी/8/2000-सामान्य

आदेश

(फरवरी, 2000 के चौथे दिन को पारित किया गया)

इस प्राधिकरण की यह उल्लिखित स्थिति रही है कि महापत्तनों में प्रशुल्क निर्धारण के मामले में एक समान सिद्धांत, दृष्टिकोण और अवधारणाएं अपनाई जानी चाहिएं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चेन्नई में फरवरी, 1998 में आयोजित कार्यशाला में अपनाए गए दिशा-निर्देश हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं।

- 2. अपनाए गए दिशा-निर्देशों में से एक इस संबंध में था कि पत्तन न्यास विलंब से की जाने वाली वापसी अदायगियों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। विशेषकर, प्रशुल्कों के आम संशोधन के संबंध में अपने प्रस्ताव के संदर्भ में तूतीकोरन पत्तन न्यास (टीपीटी) ने इस दिशा-निर्देश के क्रियान्वन के लिए हाल ही में प्रस्ताव किया था। और भी महत्वपूर्ण रूप में, टीपीटी ने अपने प्रयोक्ताओं के साथ परामर्श से इस संबंध में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव दिया था। इसका हमारे द्वारा 8 दिसंबर, 1999 को अनुमोदन किया गया था।
- 3. इस पृष्ठभूमि में, समग्र रूप में ध्यान देने के आधार पर और इस तथ्य को जानते हुए कि उक्त निर्णय में शामिल सिद्धांत/अवधारणाएं सभी महापत्तनों के लिए समान रूप में सुसंगत और वैध हैं, यह प्राधिकरण सभी महापत्तनों के लिए साझा रूप में निम्नलिखित निर्णय करता है :—
 - (i) प्रयोक्ता विलंब से किए जाने वाले भुगतानों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।
 - (ii) इसी प्रकार, पत्तन न्यास विलंब से की जाने वाली वापसी अदायगियों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर दंडात्मक ब्याज का भगतान करेगा।

- (iii) वापसी अदायिगयों में विलंब, सेवाओं की पूर्ति की तारीख से केवल 20 दिन अथवा प्रयोक्ता से अपेक्षित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, जो भी बाद में हो, गिना जाएगा।
- 4. सभी महापत्तनों (तूतीकोरन पत्तन न्यास को छोड़कर) को एतद्द्वारा अपने दरों के मान में तदनुसार उपयुक्त परिवर्तन करने का निर्देश दिया जाता है। यह आदेश भारत के राजपत्र में इसको अधिसृचित किए जाने के 30 दिन पश्चात् प्रभावी होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2000

No. TAMP/8/2000-Genl.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes penal interest on delayed payments by the users as also penal interest on delayed refunds by the Port Trust as in the Order appended hereto.

CASE NO. TAMP/8/2000-GENL.

ORDER

(Passed on this 4th day of February 2000)

It has been the stated position of this Authority to adopt uniform principles, approaches, and concepts in the matter of tariff fixation at the major ports. Towards this end, we have been guided by the Guidelines adopted at the Workshop held in Chennai in February 1998.

- 2. One of the Guidelines adopted was to the effect that the Port Trust shall pay penal interest on delayed refunds Significantly, in the context of its proposal for a general revision of tariffs, the Tuticorin Port Trust (TPT) had recently proposed implementation of this Guideline. Even more significantly, the TPT gave a consensus proposal in this regard in consultation with its users. This was approved by us on 8th December, 1999.
- 3. In this backdrop, based on a collective application of mind, and in recognition of the fact that the principles/concepts involved in the said decision are equally relevant to and valid in all the major ports, this Authority takes the following decision commonly for all the major ports:
 - (i) The user shall pay penal interest @ 24% per annum on delayed payments.
 - (ii) Likewise, the Port Trust shall pay penal interest @ 24% per annum on delayed refunds.
 - (iii) The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the user, whichever is later.
- 4 All the major ports (except the Tuticorin Port Trust) are hereby directed to introduce appropriate changes accordingly in their Scale of Rates. This Order shall come into effect 30 days after its notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, CHAIRMAN [Advt/III/IV/Exty/143/99]